



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2018/चैत्र 13, 1940

No. 128]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2018/CHAITRA 13, 1940

कार्पोरेशन बैंक

(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

मंगलवार, 17 फरवरी, 2018

सं का.प्र.प्र.आ०.सं:2469:2017-18.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 और 12 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्पोरेशन बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 में आगे संशोधन हेतु एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।
  - (2) इन विनियमों में जहाँ कहीं भी वर्णन दिया गया है उसको छोड़कर, ये विनियम 1 नवंबर, 2007 से प्रभावी माने जाएंगे।
- कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित होगा) के विनियम 3 में—
  - (i) खंड (च), के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :-

(च) "परिवार" का अर्थ अधिकारी की पत्नी/पति, पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें आश्रित सौतेला तथा कानूनन गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं), चालीस प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन और माता-पिता जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हैं और उन पर पूर्णतया आश्रित हैं।'

**स्पष्टीकरण:-** इस खण्ड का प्रयोजन अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित बच्चे या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन का अर्थ उन बच्चों या माता-पिता, भाई या बहन से है जिनकी आय प्रतिमाह ₹3,500/- से अधिक नहीं है। किंतु, यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹3,500/- प्रतिमाह से अधिक है या माता-पिता दोनों की समग्र आय ₹3,500/- प्रतिमाह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ii) खंड (ओ) को हटा दिया जाएगा

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में,

- (i) उप विनियम (4ए) को हटा दिया जाएगा;
- (ii) उप विनियम (4ए) को हटाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् –
- (5) नीचे दिए गए प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान 01 नवंबर, 2007 से लागू होंगे:

**(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी**

वेतनमान VII = ₹ 46800 – 1300/4 – 52000

वेतनमान VI = ₹ 42000 – 1200/4 – 46800

**(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी**

वेतनमान V = ₹ 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400

वेतनमान IV = ₹ 30600 – 900/4 – 34200 – 1000/2 – 36200

**(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी**

वेतनमान III = ₹ 25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500

वेतनमान II = ₹ 19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 – 28100

**(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी**

वेतनमान I = ₹ 14500 – 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – 800/7 – 25700

**स्पष्टीकरण-** 31 अक्तूबर 2007 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियमन 01 नवंबर 2007 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा,

अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियाँ, अन्यथा उप बंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तारीख को होंगी ।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है ।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में,

(क) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् –

(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अधीन, 01 नवंबर 2007 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धियाँ निम्नानुसार मंजूर की जाएंगी, अर्थात् –

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उपर्युक्त वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी ;

(ख) जो अधिकारी कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में उच्च स्तर तक पहुँचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के लिए वेतनमान की श्रेणी के लिए चले गए हैं वे प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए चार गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो प्रत्येक ₹800/- और अगले दो प्रत्येक ₹900/- होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें 01 नवंबर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि दी जाएगी और अन्य कोई गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2008 को या उसके बाद दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात उनके छँदँ : वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी ;

(ग) जो अधिकारी मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में उच्च स्तर तक पहुँचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के लिए वेतनमान की श्रेणी के लिए चले गए हैं वे प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ₹900 की तीन गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें अगली गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2007 से प्रभावी होने के साथ दी जाएगी और 01 नवंबर, 2008 को या इसके बाद आगामी

गतिरोध वेतनवृद्धि पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी :

परंतु यह भी कि मूल मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए ₹900 की चार गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

परंतु, जो अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद पहले से ही दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति तथा सेवा के तीन साल या उससे अधिक का समय पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि 01 नवंबर, 2007 को प्रदान की जाएगी और 01 नवंबर, 2008 को या इसके बाद चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी।

**स्पष्टीकरण-** इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगी।

(ख) उप-विनियम (2) में,—

(i) स्पष्टीकरण में, खंड (ड) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(च) 01 नवंबर 2007 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोधित होंगी :—

#### तालिका

जिन्होंने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण कर लिया है।	(i) अधिकतम स्केल तक पहुंचने के एक साल बाद प्रति माह ₹410/-
जिन्होंने सीएआईआईबी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं।	(i) अधिकतम स्केल पर पहुंचने के एक साल बाद प्रति माह ₹410/-
	(ii) अधिकतम स्केल पर पहुंचने के दो साल बाद प्रति माह ₹1030/-

परंतु, यदि किसी अधिकारी ने वेतन के अधिकतम स्केल तक पहुंचने के बाद, जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी (या तो कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे इस तरह की योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन के बाद जारी किश्त व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किश्त के जारी होने की तारीख के संदर्भ में होगी।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी अधिकारी ने उपरोक्त योग्यता में से कोई एक पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, तो उसे 01 नवंबर 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख जो भी बाद में है, से व्यावसायिक अर्हता वेतन प्रदान किया जा सकता है।”

(ii) टिप्पणी में, खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(v) यदि किसी अधिकारी ने, 27 अप्रैल 2010 को उक्त योग्यता में से कोई एक, जैसा कि खंड (iv) में विनिर्दिष्ट है, पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, तो उसे 01 नवंबर 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख जो भी बाद में है, से व्यावसायिक अर्हता वेतन प्रदान किया जाएगा।”

(ग) उप-विनियम (3) में, –

(i) खंड (घ) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(ङ) 01 नवंबर 2007 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, आवास किराया भत्ते के साथ-साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्न दरों पर होंगे और सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे :-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (₹)	वेतन वृद्धि घटकों पर 01.11.2007 को मंहगाई भत्ते (₹)	कुल नियत वैयक्तिक वेतन देय जहाँ बैंक का आवास प्रदान किया गया है (₹)
(क)	(ख)	(ग)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”

(ii) टिप्पणी में, खंड (i) और (ii) के लिए, निम्नलिखित खंडों को दर्ज किया जाएगा, अर्थात् :-

“(i) नियत वैयक्तिक भत्ते अथवा नियत वैयक्तिक वेतन जैसा कि खंड (ख), (ग),(घ) या (ङ) के तहत तालिका के स्तंभ (ग) के रूप में निर्दिष्ट है, उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक के साथ आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iii) आवास किराए भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ते अथवा नियत वैयक्तिक वेतन खंड (ङ) के तहत तालिका के स्तंभ (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट कुल राशि होगी और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए आवास किराए भत्ते जहाँ विनियम 4 के उप-विनियमों (2), (3), (4) या (5) में विनिर्दिष्ट वेतन के संबंधित स्केल की अंतिम वृद्धि अर्जित की जाती है।”

(iii) टिप्पणी के बाद आने वाले खंड (ङ) को उप-खंड (v) के रूप में नामित किया जाएगा और खंड (v) के लिए जैसा कि अंकित किया गया है, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) जिस अधिकारी को उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे ऊपर खंड (ख), (ग), (घ) या (ङ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात प्राप्त होगी।”

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में,

- उप-विनियम (3) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;
- उप-विनियम (4) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;
- उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों और टिप्पणियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) 01 नवंबर 2007 को या उसके बाद से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार पर  $1960=100$  के तिमाही औसत में 2838 अंकों से अधिक प्रति 4 अंकों के उत्तर या चढ़ाव के लिए महंगाई भत्ता वेतन का 0.15% देय होगा।”  
स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए,  
(क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु “वेतन” का अर्थ अवरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन होगा ।

(ख) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग), (घ), (ङ) और (च) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा ।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) और (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1) 01 नवंबर 2002 को या उसके बाद से,

(क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात् :

तालिका

जहाँ कार्यस्थल है	मकान किराया भत्ता देय होगा
(1)	(2)
(i) वर्ग ए में प्रमुख “ए” श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) वर्ग बी में क्षेत्र । और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थानों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थानों में	वेतन का 6.5%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया ऊपर स्तंभ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा ।

(2) 01 नवंबर 2007 को या उसके बाद से,

(क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.20% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

जहाँ कार्यस्थल है	मकान किराया भत्ता देय होगा
(1)	(2)
(i) वर्ग ए में प्रमुख “ए” श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) वर्ग बी में क्षेत्र । और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थानों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थानों में	वेतन का 6.5%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया ऊपर स्तंभ (2) में उल्लिखित पूर्वोक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा ।

टिप्पणी:- अपने स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े हुए मकान किराए भत्ते हेतु अधिकारियों के दावे अब मकान किराए भत्ते के 150% तक ही सीमित होंगे।”

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,

- (i) उप-विनियम (1) में, आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए “01 नवंबर 2002” को “01 नवंबर 2007” के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (2) में, आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए “01 नवंबर 2002” को “01 नवंबर 2007” के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप-विनियम (3), (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

- (3) 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी ग्रुप ए या ग्रुप बी की किसी परियोजना क्षेत्र में सेवारत है तो, वह निर्धारित ग्रुप ए या ग्रुप बी में क्रमशः ₹290 प्रतिमाह या ₹255 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (4) 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है और यदि पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे स्कूल अथवा कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो उसे दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सभी बच्चों के लिए ₹700/- प्रति माह का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता देय होगा, परंतु पूर्ववर्ती स्थान में सभी बच्चों द्वारा अध्ययन समाप्त करने पर उस भत्ते का भुगतान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
- (5) 1 मई 2010 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलिंग्वियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है, विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75% अधिकतम ₹2300/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते।

परंतु, यदि उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम ₹1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

परंतु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति किया जाता है, उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम ₹1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।”

- (iv) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(8) 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का एक दिन का कार्य-समय दो घंटों के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित होता है तो वह ₹165/- प्रति माह की दर से विभाजित छूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।”

(v) उप-विनियम (10) में,

- (क) आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए, “01 नवंबर 2002” को “01 नवंबर 2007” के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

#### तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान और मरकारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम ₹550/- प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 2½% अधिकतम ₹680/- प्रतिमाह
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम ₹1570/- प्रतिमाह

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, खंड (क) के लिए उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) चिकित्सा सहायता - 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित श्रेणी में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी अपने एवं अपने परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट राशि का पात्र होगा। यह प्रतिपूर्ति अधिकारी द्वारा दिए गए स्वयं के प्रमाण-पत्र में उल्लेखित व्यय विवरण के अनुरूप की जाएगी, अर्थात् :-

#### तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	₹5100/- या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	₹6320/- या वास्तविक व्यय, इनमें जो भी कम हो

टिप्पणी:- (i) अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जो किसी भी समय दी जाने वाली उपर्युक्त अधिकतम राशि की तीन गुने से अधिक न हो, या

(ii) वर्ष 2007 के लिए, चिकित्सा सहायता के अधीन चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो महीनों अर्थात् नवंबर 2007 और दिसंबर 2007 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएंगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य के लिए,

(i) जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो उन सभी मामलों में अधिकारी के लिए 100% और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 75% तक चिकित्सालयवास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, या

(ii) 01 मई 2010 को या उसके बाद से, इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी के चिकित्सालयवास व्ययों की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौता दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के अंतर्गत दिए गए चिकित्सालयवास योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा, बशर्ते वे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सीमा के अधीन हो, अर्थात् :-

#### तालिका

<p>(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान । और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥ एवं ॥॥</p>	<p>(i) विस्तर शुल्क स्वयं – ₹700/- प्रति दिन परिवार – ₹525/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 125% के मान पर</p>
<p>(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV एवं V और उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII</p>	<p>(i) विस्तर शुल्क स्वयं – ₹900/- प्रति दिन परिवार – ₹675/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 150% के मान पर।”</p>

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप-विनियमन (1) में किसी बात के बावजूद, यदि वैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01 नवंबर 2007 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.20% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, इनमें जो भी कम हो, भुगतान करेगा :

परंतु जहाँ ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ वैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.25% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी :

परंतु यह भी कि जहाँ वैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहाँ बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे ।”

10. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) 01 मई 2010 से प्रभावी होने पर, 12 महीनों की समग्र अवधि के भीतर, अधिकतम 45 दिनों तक गर्भाशयोच्चेदन के मामले में छुट्टी भी दी जा सकती है ।”

11. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, खंड (क) के लिए उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) विराम भत्ता – 01 मई 2010 को और उसके बाद से, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में निर्धारित श्रेणी या वेतनमान में एक अधिकारी, प्रतिदिन स्तंभ (2) में निर्धारित की गई दरों पर ‘विराम भत्ता’ पाने का हकदार होगा, अर्थात् :-

### तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/ वेतनमान	प्रमुख ‘ए’ वर्ग के नगर	क्षेत्र-।	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	₹	₹	₹
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I / II / III के अधिकारी	800	700	600

परंतु, वेतनमान IV और उनसे उच्च अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों यानि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में बाहरी कार्य के दौरान प्रतिदिन ₹1200/- और वेतनमान । या ॥ या ॥। के अधिकारियों के लिए प्रतिदिन ₹1000/- की दर से विराम भत्ता देय होगा :

परंतु यह भी कि, यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो, ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा ।

**स्थैतिकरण** – विराम भत्ता की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी । यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो 'प्रतिदिन' का अभिप्राय होगा, ऐसी अवधि जो 8 घंटे से कम नहीं है।'

12. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) 01 मई 2010 को या उसके बाद से, स्थानांतरण पर जाने वाला कोई अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, यात्री सामान का बीमा आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा, अर्थात् :-

### तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	₹12000
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	₹9000"

13. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु, 01 मई 2010 से प्रभावी, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान । में एक अधिकारी, जो छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा रहा है, सबसे कम किराया अर्थव्यवस्था वर्ग में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा, उस स्थिति में वास्तविक किराया या यात्रा की दूरी के लिए ट्रेन द्वारा ऐसी प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया, जो भी कम है, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और समान नियम मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ॥ व ॥। के अधिकारी के लिए भी लागू होंगे, जो छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा रहा है, जहाँ यात्रा की दूरी 1000 किमी. से कम है ।"

14. उक्त विनियमों के विनियम 45 में,

(i) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह कि 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंकों की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा।”

(ii) उप-विनियम (3) में, खंड (ख) के बाद और टिप्पणी के पहले, निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत कवर किए गए अधिकारियों, जो पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं देते हैं, अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत जारी रहेंगे।”

(iii) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) 01 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों को एक निश्चित अंशदायी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा, जहाँ अधिकारी 10% वेतन और महंगाई भत्ते का योगदान देगा तथा बैंक, भारत सरकार की अधिसूचना फा.सं.5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 जैसा कि समय-समय पर संशोधित है, के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना (एनपीएस) में, अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार समान राशि का योगदान देगा।

15. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची

[विनियम 23 का उप-विनियम (ii) देखें]

01 नवंबर, 2007 से एक अधिकारी, विशेष क्षेत्रीय भत्ता जो उसे वापस लेने तक या पूर्ण या पाक्षिक रूप से संशोधन करने के समय तक, के लिए पात्र होगा जो तालिका में निम्नवत् दर्शाया गया है, जैसे :-

### तालिका

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	₹14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
1.	मिजोरम (क) मिजोरम का चिंपतुर्ईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलाई जिले के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र	2000	2600
	(क) मिजोरम के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लुंगलाई जिला	1600	2100
		1200	1500
	(ग) मिजोरम का संपूर्ण आईजोल जिला		

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	₹14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह  (क) उत्तर एवं मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नारकोडम द्वीप समूह  (ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	2000  1600	2600  2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा  (क) त्रिपुरा के दुष्कर क्षेत्र  (ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा त्रिपुरा	1600  2000	2100  1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश  (क) अरुणाचल प्रदेश के दुष्कर क्षेत्र  (ख) दुष्कर क्षेत्रों को छोड़कर सारा अरुणाचल प्रदेश	2000  1600	2600  2100
11.	जम्मू और कश्मीर (क) कठुआ जिला : नियावत बानी, लोही, मलहार और मछोड़ी  (ख) उधमपुर जिला : (i) दुड़ु बसंतगढ़, लांडर भामाग इलाका, इनके अलावा जो भाग 2(ख) में सम्मिलित थे । (ii) मोहरे तहसील के कंबन पक्ष से गोयल तक के क्षेत्र तथा कियासी पक्ष से अर्नास तक के क्षेत्र ।	2000	2600

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	₹14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
	(ग) डोडा जिला : किश्तवार तहसील के नियावत नोगाम तथा पद्दर के इलाके (घ) लेह जिला : जिले के सभी स्थान (ङ) वारामुला जिला : (i) संपूर्ण गुरेज-निरावत, तंगदर उप-मंडल तथा केरन इलाका (ii) मध्यिल (च) पूँछ तथा रजौरी जिला : पूँछ तथा रजौरी शहर और सुंदरबनी एवं दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूँछ तथा रजौरी जिले के क्षेत्र (छ) उपर्युक्त (क) से (च) में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी की दूरी में आने वाले ऐसे स्थान जहाँ सीमा भत्ते के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय-समय पर पात्र घोषित किया गया है।	2000	2600
		2000	2600
		2000	2600
		1600	2100
		1200	1500
		1200	1500
12.	हिमाचल प्रदेश (क) चंबा जिला (i) पंगी तहसील, भारमौर तहसील, पंचायत: बडगांव, बजोल, दओल कुगटी, नया गांम तथा टुंडा, गाँव: जगत ग्राम पंचायत का घाट, चौहाता ग्राम पंचायत का कनारसी	2000	2600
	(ii) भरमौर तहसील, उपर्युक्त मद (i) में शामिल गावों एवं पंचायतों को छोड़कर	1600	2100
	(iii) भटियाट तहसील का झंडू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (वनिखेत सहित)	1200	1500
	(ख) किन्नौर जिला : (i) आश्रंग, चिट्कुल तथा हांगो कुनो/चरंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नथपा तथा रुपी के ग्राम पंचायत हैं, पूँह सब- डिविजन, उक्त विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्र को छोड़कर। (ii) उपर्युक्त (क) में शामिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिले	2000	2600
		1600	2100

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	₹14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
	<p>(ग) कुल्लू जिला :</p> <p>(i) निर्मांद तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें खर्गा, कुशवार तथा सर्गा ग्राम पंचायत शामिल हैं।</p> <p>(ii) आउटर-सेराज (निर्मांद तहसील के बरौ तथा जकत-खाना के गावों को छोड़कर) तथा संपूर्ण जिला (पंड्रिबिस के परगना तथा आउटर सेराज क्षेत्र को छोड़कर किंतु निर्मांद तहसील के बरौ एवं जगत-खाना गांव को शामिल कर)</p> <p>(घ) लाहौल तथा स्पिति जिला :</p> <p>लाहौल तथा स्पिति के संपूर्ण क्षेत्र</p> <p>(ङ) शिमला जिला :</p> <p>(i) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा तथा चडी-ब्रांदा के पंचायत शामिल हैं।</p>	2000	2600
	<p>(ii) दोरा-कावर तहसील, रामपुर का दरकली ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील तथा मुनिश, परगना सराहान का घोरी चाइबिस।</p> <p>(iii) चोपल तहसील तथा घोरिस, पंजगांव, पाटस्त्रौ, नौविस तथा सरहन परगना का तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र का घोती ग्राम पंचायत, परगना बराबिस, रामपुर कस्बा तथा रामपुर तहसील के परगना रामपुर का घोरी नोग, शिमला शहर तथा उसके उपनगर (धाली, जटोग, कसुमपती, मशोब्रा, तारादेवी एवं टुटु)</p>	1600	2100
	<p>(च) कांगड़ा जिला :</p> <p>(i) बड़ा भंगल तथा छोटा भंगल के क्षेत्र</p>	1600	2100

क्रम संख्या	ऐसा स्थान जहाँ भत्ता देय होगा	देय भत्ते की दर	
		₹ 14,700 से कम वेतन के लिए	₹14,700 से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
	(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा धर्मशाला शहर में शामिल किंतु नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय – महिला आईटीआई, दारी, मेकनिकल वर्कशोप, रामनगर, बाल कल्याण तथा शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशोप, सधेर, मंडल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच सब-डिविजन, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर । कांगड़ा जिले के पालमपुर टाउन, पालमपुर में एचपीकेवीवी कैंपस और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, किंतु पालमपुर टाउन में शामिल- एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/ इंडो-जर्मन कृषि वर्कशोप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुन्दला, इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन, लोहाना, डी.पी.ओ. निगम, बुन्दला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिवीजन, घुगर ।	1200	1500
	(छ) मंडी जिला : जोगिंदर नगर तहसील का छुहर घाटी, थुनाग के पंचायत बागड़ा, छत्री, छोटधार, गरगुशैन, गटू, गर्यास, जंजेली, जर्यार, जोहर, कलहनी, कल्वान, खोलनाल, लोथ, सिलिवागी, सोमचान, थछधार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक के पंचायत- बिंगा, कामला, सकलाना, तन्यार तथा ताराखोला, कर्सोंग तहसील के पंचायत- बलिधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहूदी, मंज, पेखी, मैंज, साराहन और तेबान, सुंदरनगर तहसील के पंचायत- बोही, बटवारा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी, शोजा ।	1200	1500
	(ज) सिरमौर जिला : बनी, बखाली (पाल्हड तहसील), भडोग, भेनेडी (पौंटा तहसील), बिडला (नाहन तहसील), डिब्बड (पाल्हड तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) के पंचायत ।	1200	1500
	(i) सोलन जिला : मंगल पंचायत (झ) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त मद (क) से (i) में शामिल नहीं है ।	1200 320	1500 400

13.	उत्तराखण्ड चमौली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग और चंपावती जिले के क्षेत्र।	2000	2600"
-----	---	------	-------

### विवरणात्मक ज्ञापन

ऐसे विनियमों जिनको पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे विशिष्ट जनादेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच, संबंधित बैंकों और बैंकों के शीर्ष स्तर के अधिकारी संघ द्वारा दिए गए संयुक्त नोट पर हस्ताक्षरित नियमों एवं शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पी.वी. हेमचंद्र राव, सहायक महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./02/18 ]

**नोट:** मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 30.09.2000 को प्रकाशित किए गए और बाद में निम्न दिनांकों को प्रकाशित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

1. 01.02.2006
2. 23.09.2006
3. 15.01.2011
4. 01.11.2014

### CORPORATION BANK

(A Premier Public Sector Bank)

(HEAD OFFICE)

### NOTIFICATION

Mangalore, the 17<sup>th</sup> February, 2018

**No. PAD:IR:2469:2017-18**—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the Corporation Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Corporation Bank (Officers') Service Regulations, 1982, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Corporation Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
2. In the Corporation Bank (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(g) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation - For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month:

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’

(ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

- (i) sub-regulation (4A) shall be omitted;
- (ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800

## (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

## (c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5— 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

## (d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

**Explanation.-**Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31<sup>st</sup> October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1<sup>st</sup> November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”.

## 4. In regulation 5 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

(c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1<sup>st</sup> November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

(b) in sub-regulation (2),-

(i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale.  (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1<sup>st</sup> November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) if an officer, as on the 27<sup>th</sup> April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

(c) in sub-regulation (3),-

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”,

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:-

“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, -

- (i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;
- (ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;
- (iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:-

“(5) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,-

- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(1) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2002,

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay

(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2) on and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely: -

TABLE

<b>Where the place of work is in</b>	<b>HRA payable shall be</b>
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

**Note.** The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,-

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
  - “(3) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
  - (4) On and from the 1<sup>st</sup> day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
  - (5) On and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

(iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-  
“(8) on and from the 1<sup>st</sup> day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;

(v) in sub-regulation (10),-

(a) for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November 2002”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of November, 2007” shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

**“TABLE**

<b>Place (1)</b>	<b>Rate (2)</b>
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1<sup>st</sup> day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

## TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement	
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less	
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less	

**Note.** (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. - for the purposes of this regulation,-

(i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;

(ii) on and from the 1<sup>st</sup> day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27<sup>th</sup> day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self – Rs.700 per day Family – Rs.525 per day  (ii) Other charges At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self – Rs.900 per day Family – Rs.675 per day  (ii) Other charges At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(3) With effect from the 1<sup>st</sup> day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to “per diem” Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers (1)	Major ‘A’ Class cities (2)	Area I	Other Places
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with effect from the 1<sup>st</sup> May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, -

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22<sup>nd</sup> December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

“Schedule to Corporation Bank (Officers') Service Regulations, 1979  
[See sub-regulation (ii) of regulation 23]

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	<b>Mizoram</b>		
	(a) Chimtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	<b>Nagaland</b>	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
3.	<b>Andaman and Nicobar Islands</b>		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	<b>Sikkim</b>	2000	2600
5.	<b>Lakshadweep Islands</b>	2000	2600
6.	<b>Assam</b>	320	400
7.	<b>Meghalaya</b>	320	400
8.	<b>Tripura</b>		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	<b>Manipur</b>	1200	1500
10.	<b>Arunachal Pradesh</b>		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	<b>Jammu and Kashmir</b>		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:  (i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).  (ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	2000	2600
	(c) Doda District:  Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(d) Leh District :  All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District  (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua  (ii) Matchill	2000 1600	2600 2100
	(f) Poonch and Rajouri District :  Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	<b>Himachal Pradesh</b>  (a) Chamba District  (i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata  (ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	2000 1600	2600 2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:  (i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.  (ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	2000 1600	2600 2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District :		
	(i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumptoni, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District:		
	(i) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakhola, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja. (h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(i) Solan District : Mangal Panchayat. (j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	1200	1500
13.	<b>Uttarakhand</b> Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	320	400
		2000	2600”

### **EXPLANATORY MEMORANDUM**

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

**P. V. HEMACHANDRA RAO, Assistant General Manager**

[ADVT.-III/4/Exty./02/18]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India on 30.09.2000 and subsequently amended vide notifications published on:

1. 1.02.2006
2. 23.09.2006
3. 15.01.2011
4. 01.11.2014